(b) For the Seventh Five Year Plan, an amount of Rs. 107.38 crores has been allocated to Orissa for the rural electrification programme. Against this, a sum of about Rs. 71 crores has been disbursed by Rural Electrification Corporation to Orissa State Electricity Board upto February, 1989.

(c) The Planning Commission has fixed a target of electrification of 785 villages in Orissa during 1989-90.

(d) The remaining villages are expected to be electrified by the end of 8th Five Year Plan subject to availability of resources and other inputs.

500 MW unit in Korba

2870. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) by when the third 500 MW unit in Korba is likely to be commissioned;

(b) what will be the total capacity of this unit after commissioning the unit;

(c) whether it is a fact that the electricity generated at Korba is not being fully utilised and generation is contemplated to be curtailed; and

(d) if so, what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) The third 500 MW unit at Korba has been synchronised on 23rd March, 1989.

(b) The total capacity of the Korba Super Thermal Power Station is 2100 MW after commissioning of this unit.

(c) and (d) The electricity generated at the Korba Super Thermal Power Station is being fully utilised as per the system requirements in the Western Regional power grid. The gross generation from this Station during the period April, 1988 to February, 1989 was 6891 million units as against the proportionate target of 6598 million units.

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत गृहों की स्थापना

2871. **श्री अजीत जोगी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भण्डार (ग्वालियर), झाबेरा, राजगढ़ और गुना में 300 मेगावाट पावर की उत्पादन क्षमता वाले गैस पर आधारित विद्युत गृहों की स्थापना के प्रस्ताव भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) गैस पर आधारित विद्युत गृहों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में मध्य प्रदेश में होने वाली बिजली की संभावित कमी को देखते हुए क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र कोई निर्णय लेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में केन्द्रीय विद्युत-प्राधिकरण की निम्नलिखित स्कीमें प्राप्त हुई हैं :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1.	ग्वालियर गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ता० विद्युत केन्द्र (ता० वि० केन्द्र)	3×100 मे. वा. जीटी+ 1×150 मे. वा. एसटी	420.30
2.	झाबुआ गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ता. वि. केन्द्र	3×100 मे. वा. जीटी+ 1×150 मे. वा. एसटी	428.40
3.	राजगढ़ गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ता. वि. केन्द्र	3×100 मे. वा. जीटी+ 1×150 मे. वा. एसटी	432.90
4.	गुना गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ता. वि. केन्द्र	3×100 मे. वा. जीटी+ 1×150 मे. वा. एसटी.	414.00

ईंधन लिंकेज सुनिश्चित किए जाने, अपेक्षित निवेशों की पुष्टि हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात प्रस्ताव पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति/निवेश संबंधी निर्णय के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

मध्य प्रदेश में शहरों में टेलीफोन सेवाओं का विस्तार

2872. **श्री अजीत जोगी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1988–89 वर्ष के दौरान भोपाल, जबलपुर, और रायपुर शहरों में क्रमशः 4000, 500 और 300 टेलीफोन केन्द्र लाइनों के विस्तार का लक्ष्य था ;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) मध्य प्रदेश के इन शहरों में और इन्दौर और ग्वालियर में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान लाइनों के विस्तार का लक्ष्य क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) वर्ष 1988–89 के दौरान, भोपाल, टेलीफोन प्रणाली का 6000 लाइनों का विस्तार किया गया है जबकि 4000 लाइनों तक विस्तार किए जाने की योजना थी। जबलपुर एक्सचेंज का 500 लाइनों तक विस्तार किया गया है और रायपुर एक्सचेंज का 31–3–89 तक 300 लाइनों तक विस्तार किए जाने की आशा है जबकि चालू वर्ष के लिए इनके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) वर्ष 1989–90 के दौरान, मध्य प्रदेश में स्विचन क्षमता की (कुल) 25,000 लाइनें और जोड़े जाने का प्रस्ताव है। उपस्कर की अनुपलब्धता के कारण 1989–90 के दौरान इन्दौर और ग्वालियर एक्सचेंजों का विस्तार करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इन्दौर में 10,000 लाइनों तथा ग्वालियर में 5000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। भोपाल के वर्तमान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज का 1989–90 में 4000 लाइनों तक विस्तार किए जाने की संभावना है। रायपुर में 1989–90 के दौरान 6000 लाइनों की क्षमता का एक नया इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जबलपुर में, आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में, 5000 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है।